ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), CHHATTISGARH)

To,

The -1

GINNI DEVI GOEL FOUNDATION

Khasra no. 352/29,37/6 Vill. Parsulidih&Baronda, Tehsil Dharsiwa, Raipur (C.G.) -493111

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/CG/INFRA2/435032/2023 dated 30 Jun 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC24B038CG128448**
2.	**File No.**	OL/EC/INFRA2/RAIPUR/2546
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	8(a) Building and Construction projects
6.	**Name of Project**	500 bedded Hospital project (Phase -1 : 300 beds & Phase - 2 : 200 beds), "Gini Devi Goel Manipal Hospitals" proposed by Ginni Devi Goel Foundation
7.	**Name of Company/Organization**	GINNI DEVI GOEL FOUNDATION
8.	**Location of Project**	CHHATTISGARH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 04/06/2024

(e-signed)
P Arun Prasad
Member Secretary
SEIAA - (CHHATTISGARH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल: seiaacg@gmail.com

क.572/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./बिल्डिंग/2546 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक21/5/2024

प्रति,

मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन,
(गिनी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल्स),
C/o, सुरेश गोयल एण्ड ब्रदर्स,
न्यू टिम्बर मार्केट, फाफाडीह, रायपुर,
जिला–रायपुर (छ.ग.) 492009

विषय :– ग्राम–परसुलीडीह एवं बरोंदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर में ग्राम–परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम–बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4, 45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर, कुल बिल्टअप एरिया 42,489.63 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ऑनलाईन प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/ 435032/ 2023, दिनांक 30/06/2023 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 11/01/2024।

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र 30/06/2023 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 11/01/2024 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/ 435032/ 2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित हॉस्पिटल ग्राम–परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम–बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4,

45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप एरिया–42,489.63 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 120 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये है। ऑनलाईन आवेदन के दौरान त्रुटिवश फार्म में 250 करोड़ रूपये का उल्लेख हो गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रोजेक्ट की लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है। अतः परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रूपये मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। समिति का मत है कि निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन के नाम पर है।

4. **लेण्ड यूज स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर में से सड़क मार्ग की चौड़ाई के कारण 845.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा।

S.No.	Land use	Area (sq.m)	Percentage (%)
1.	Ground Coverage area	11,342.30	30.00
2.	Internal roads and pathway	16,721.60	44.23
3.	Open Parking area	5,962.40	15.77
4.	Green Belt area	3,780.80	10.00

	Total	**37,807.52**	**100**

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (sq.m)
1.	Hospital Building	27,755.21
2.	Nursing College	2,482.48
3.	Hotel Block	2,451.62
4.	Nursing Hostel	1,416.17
5.	Doctors Apartment	1,335.28
6.	Total Built-up Area (A)	35,440.76
7.	Total Parking (B)	7,048.87
	Total (A+B)	**42,489.63**

6. फ्लोर संबंधी विवरण –

S.No.	Floor	Area in Sq.m						
		Hospital Building	Nursing college	Hotel block	Nursing hostel	Doctors apartment	Total Built-up area (A)	Total Parking (B)
1.	Basement – 2 (BUP – 1610.92 + Stack parking – 3042.68 Sq.m)	1610.92	--	--	--	--	1610.92	3042.68
2.	Basement – 1 (BUP – 1979.96 + Stack parking – 2496.53 Sq.m)	1979.96	--	--	--	--	1979.96	2496.53
3.	Ground floor (Parking) / Stilt floor	--	544.99	553.48	--	411.19	--	1509.66
4.	Ground Floor	3563.20	--	--	458.31	--	4021.51	

Earth Protects if She is Protected

5.	Floor - 1	4214.81	663.72	676.71	320.06	333.82	6209.12	
6.	Floor - 2	3740.34	454.69	437.27	318.90	333.82	5285.02	
7.	Floor - 3	3654.85	454.69	445.88	318.90	333.82	5208.14	
8.	Floor - 4	2984.74	454.69	445.88	--	333.82	4219.13	
9.	Floor - 5	2984.74	454.69	445.88	--	--	3885.31	
10.	Floor - 6	3021.65	--	--	--	--	3021.65	
	Total	**27755.21**	**2482.48**	**2451.62**	**1416.17**	**1335.28**	**35440.76**	**7048.87**

7. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 3,000 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।
9. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Basement-1, Basement-2 एवं Ground floor में वाहनों के पार्किंग हेतु गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 354 Equivalent Car Space (ECS) की आवश्यकता होगी। उक्त हेतु 605 Equivalent Car Space (ECS) रखा जाना प्रस्तावित है।
12. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।
13. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** –

S.N.	Waste	Quantity	Disposal
1.	Municipal Solid Waste	1,192.5 Kg/day	The garbage will be segregated at source through collection bins into Bio-degradable waste and Non Bio-degradable waste. Plastic waste will be given to the waste recyclers and bio-degradable waste will be disposed to the Municipal corporation bins. Kitchen and food waste generated will be bio-composted within the project site premises and will be used as manure for greenbelt development.
2.	Bio-medical	187.5	Will be disposed as per Bio-Medical

	waste	Kg/day	Waste (Management & Handling) Rules
3.	Sludge from STP	42.7 Kg/day	Stored in HDPE bags and will be used as manure /given to farmers.
4.	Waste Oil	100 Liter / Annum	Will be given to SPCB approved vendors.

14. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन –**

Category	Quantity	Types of waste	Disposal
Yellow	approx 108.75 kg/day	Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes.	Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Red	approx 37.5 kg/day	Contaminated plastic wastes.	Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
White	approx 11.25 kg/day	Waste sharps including metals.	Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Blue	approx 30 kg/day	Metallic body Implants and glasswares.	Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Total	**187.5 kg/day**		

15. अस्पताल में जनित होने वाले ई–वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

16. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 497 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 228 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 129 घनमीटर प्रतिदिन, किचन हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन, लैब हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, लाउण्ड्री हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर वाशिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन तथा फिल्टर/आर. ओ. बेक वॉश 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति नगर पालिका/भू–जल के माध्यम से की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति हेतु पाईप लाईन कनेक्शन के लिए जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति हेतु अनुमति संबंधी

जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – कंस्ट्रक्शन फेज में दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशनल फेज में दूषित जल की मात्रा 427 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 2 नग 250 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत स्क्रीनिंग, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सीवेज कलेक्शन कम इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबीआर रिएक्टर, टव्यूब सेटल्र, सर्ज टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज ड्राईंग बेड/स्लरी कलेक्शन टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर फ्लशिंग, वृक्षारोपण आदि हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष दूषित जल को नगर पालिका के ड्रेन में डिस्चार्ज किया जाएगा। समिति का मत है कि डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,505.18 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 13 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

17. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 4,500 के.डब्ल्यू.एच. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु 3,780.8 वर्गमीटर (10 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि परिसर

के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। कुल रूफ एरिया के एक तिहाई भाग में सोलर पैनल की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12000	2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr.	230	Following activities at Proposed Land	
			Eco Park Nirman	230
			Total	**230**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ईको पार्क निर्माण'' हेतु उपयुक्त प्रस्ताव (गणना सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईको पार्क निर्माण हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता के संबंध में संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन एवं सरपंच ग्राम पंचायत बरोंदा तथा नगर निगम, रायपुर को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ईको पार्क निर्माण'' के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोंदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

2. निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्तावित परियोजना के ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

6. अस्पताल में जनित होने वाले ई–वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. जल की आपूर्ति की अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

8. डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

11. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ईको पार्क निर्माण'' के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (कम से कम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोंदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के बैठक क्रमांक 484वीं, दिनांक 25/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 02/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रूपये की विस्तृत जानकारी सहित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के नाम एवं दूरी का उल्लेख करते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्रस्तावित परियोजना के ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया गया है।

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन कमांक 2588/नग्रानि/धारा–29/सी.जी./आर.पी.आर./टी.एन.सी.पी./2023/ 0051/2023 रायपुर, दिनांक 23/08/2023 द्वारा कुल रकबा 3.932 हैक्टेयर हेतु जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से 03 वर्ष तक प्रभावशील है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन कमांक /सी.जी./आर.पी.आर./बी.पी.सी./2023/0496/2023, दिनांक 05/10/2023 द्वारा कुल बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर हेतु जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से 03 वर्ष तक प्रभावशील है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है,

जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले ई–वेस्ट का अपवहन सी.पी.सी.बी./एस.पी.सी.बी. के ई–वेस्ट (मैनेजमेंट) नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का अपवहन सी.पी.सी.बी./एस.पी.सी.बी. के बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले रेडियोलॉजी वेस्ट का अपवहन बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

7. जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,250 के.व्ही.ए. का 3 नग डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा, जिसकी चिमनी की ऊंचाई सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप रखी जाएगी।

10. परिसर के भीतर 300 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,40,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,40,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 21,90,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयुक्त, नगर निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 565, कुल रकबा 5 एकड़ में से 2.8 एकड़) में कुल 34,000 नग पौधों के वृक्षारोपण किये जाने एवं 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण अनुसार कुल राशि 1,34,69,156 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये की शेष राशि 95,30,844 रूपये का अन्य स्थान पर ईको पार्क का पृथक से विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के नाम एवं दूरी का उल्लेख करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये में से राशि 1,34,69,156 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है। शेष राशि 95,30,844 रूपये का अन्य स्थान पर ईको पार्क का पृथक से विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी. आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम–बरोदा 1.6 कि. मी., अस्पताल ग्राम–बरोदा 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी., राज्यमार्ग 29 कि.मी., नहर 900 मीटर दूर है।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के समय कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर प्रदर्शित किया गया था जो कि प्रस्तावित क्षेत्रफल था, तदानुसार विकास अनुज्ञा के लिए भी आवेदन किया गया था किन्तु विकास अनुज्ञा में प्रस्तावित रोड के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त रकबा 0.067 हेक्टेयर जो की पहले से ही संस्थान के अधिग्रहण में है, को सम्मिलित किया गया है। जिससे कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर विकास अनुज्ञा में दर्शित हुआ है।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए आवेदन किया गया है, जिसमे अस्पताल के अलावा अन्य भवन (नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल, डॉक्टर ब्लॉक इत्यादि) का बिल्टअप क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है, किन्तु वर्तमान व्यावसायिक व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रारम्भिक वर्षों में केवल अस्पताल का ही निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा कुल बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर के लिए ही आवेदन किया गया था एवं तदनुसार सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई हैं।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">12000</td><td rowspan="4">2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr.</td><td rowspan="4">230</td><td colspan="2">Following activities at Proposed Land</td></tr>
<tr><td>Miyawaki Plantation</td><td>134.69</td></tr>
<tr><td>Oxyzone cum recreational park</td><td>95.31</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>230</td></tr>
</table>

5. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रुपये के निवेश की कार्ययोजना – आवेदित संस्थान को सी.ई.आर. के तहत् कुल रकबा 5 एकड़ भूमि खसरा नं. 565 खमतराई ग्राम गोंडवरा, पटवारी हल्का नं.–00037, राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर 5 भनपुरी, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में रायपुर नगर निगम के द्वारा पत्र के माध्यम से आबंटित की गई हैं, जिसमें से परियोजना क्रमांक 1 के अनुसार कुल राशि 1,34,89,156 रुपये के व्यय से कुल रकबा 2.8 एकड़ भूमि में मियावकी पद्धति के अनुरूप 34,000 वृक्षारोपण किया जायेगा।

परियोजना क्रमांक 2 के अनुसार शेष भूमि 2.2 एकड़ में कुल राशि 95,30,844 रुपये के व्यय से एक ऑक्सीजोन एवं मनोरंजन पार्क का निर्माण किया जायेगा। उक्त ऑक्सीजोन एवं मनोरंजन पार्क के निर्माण हेतु रायपुर नगर निगम के द्वारा पत्र के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई हैं, जिसके अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत ''ऑक्सीजोन कम रिक्रियेशन पार्क'' के तहत् (आम, जामुन, अमरूद, आंवला, पीपल, नीम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार (1) प्रथम वर्ष में 2,500 नग पौधों के लिए राशि 10,00,000 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 15,00,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 6,30,000 रूपये, ईको पार्क निर्माण (बेंच, झुला, लेण्ड स्कैपिंग, पाथवे, ड्रिकिंग वाटर फेसिलिटी, टॉयलेट्स, सोलर लाईट्स) के लिए राशि 18,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 49,30,000 रूपये तथा (2) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 2,500 नग प्रतिवर्ष पौधों के लिए राशि 10,00,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 6,50,844 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 16,50,000 रूपये प्रतिवर्ष (3) चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में रख–रखाव के लिए राशि 6,50,000 रूपये प्रतिवर्ष, इस प्रकार 05 वर्षों हेतु कुल राशि 95,30,844 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन (गिनी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल्स) को ग्राम–परसुलीडीह एवं बरोंदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर में ग्राम–परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम–बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4, 45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर, कुल बिल्टअप एरिया 42,489.63 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/04/2024 को संपन्न 172वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन (गिनी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल्स) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

i. सी.ई.आर. के तहत् एवं परियोजना परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत मियावकी पद्धति के अनुरूप वृक्षारोपण एवं ''ऑक्सीजोन कम रिक्रियेशन पार्क'' तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग

फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

iv. वर्तमान में सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा कुल बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर के लिए है। अतः बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर हेतु निर्माण कार्य किया जाना होगा। शेष बिल्टअप क्षेत्र 16,153.45 वर्गमीटर हेतु नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जाए। शेष बिल्टअप क्षेत्र 16,153.45 वर्गमीटर हेतु नगर तथा ग्राम निवेश से बिना अनुमति के निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार ग्राम–परसुलीडीह एवं बरोंदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर में ग्राम–परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम–बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4, 45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर, कुल बिल्टअप एरिया 42,489.63 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

ii. Project proponent shall only start the construction of project upto builtup area of 26,336.18 m^2. Project proponent shall not exceed the construction builtup area 26,336.18 m^2 without prior building permission from Nagar Nigam. Project proponent shall only start the contruction of builtup area more than 26,336.18 m^2 after prior building permission from Nagar Nigam.

iii. The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur.(If required)

iv. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.

v. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

vi. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.

vii. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

viii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

ix. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.

x. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$) covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust sprinkling, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water Quality Monitoring And Preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rainwater.

ii. Design of Buildings shall follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.

iii. At the time of operation phase, the total water requirement shall not exceed the capacity of 497 m^3/day.

iv. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

v. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

vi. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

vii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan

viii. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

ix. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

x. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xi. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-

harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.

xii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.

xiii. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xiv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

xv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.

xvi. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, oil/ grease trap, sewage collection cum equilization tank, MBBR tank, Tube settler, surge tank, pressure sand filter, activated carbon fitler, filter press and sludge drying bed/slurry collection tank) with tertiary treatment. Project proponent shall intall chlorine dosing tank for disinfection. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening after disinfection. Waste water generated from the hospital shall be treated in Effluent treatment plant (ETP). The treated effluent from ETP shall be recycled/re-used for flushing. Project proponent shall intall chlorine dosing tank for disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

xvii. The capacity of Sewage Treatment Plant Capacity shall not be less than 500 m^3/day (2x250 m^3/day).

xviii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xix. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.

xx. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.

xxi. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality

shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.

ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.

iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities.The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003, 25th January, 2016 and 31st December 2021. Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Bio-Medical Waste Management

i. Project proponent shall follow all the provisions of the Bio-medical Waste Management Rules, 2016(as amended).

ii. Project proponent shall obtain Bio-medical authorization from Chhattisgarh Environment Conservation Board under the provisions of the Bio-medical Waste Management Rules, 2016 (as amended).

Category	Types of waste	Disposal
Yellow	Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes etc.	Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Red	Contaminated plastic wastes etc.	Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
White	Waste sharps including metals etc.	Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Blue	Metallic body Implants and glasswares etc.	Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.

VIII. Green Cover

i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).

ii. Green belt shall be developed in an area equal to 10 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, aved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

IX. Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.

   b. Traffic calming measures.

   c. Proper design of entry and exit points.

   d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

X. Human Health Issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

XI. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12000	2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr.	230	Following activities at Proposed Land	
			Miyawaki Plantation	134.69
			Oxyzone cum recreational park	95.31
			Total	**230**

Development of "Pavitra-van Nirman" in khasra no. 565 area of 2.8 acre as dense and religious plantaion.

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be

submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XII. Additional Conditions

i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the

date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The procedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the procedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

xx. सी.ई.आर. के तहत् एवं परियोजना परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

xxi. सी.ई.आर. के अंतर्गत मियावकी पद्धति के अनुरूप वृक्षारोपण एवं ''ऑक्सीजोन कम रिक्रियेशन पार्क'' तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

xxii. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

xxiii. वर्तमान में सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा कुल बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर के लिए है। अतः बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर हेतु निर्माण कार्य किया जाना होगा। शेष बिल्टअप क्षेत्र 16,153.45 वर्गमीटर हेतु नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जाए। शेष बिल्टअप क्षेत्र 16,153.45 वर्गमीटर हेतु नगर तथा ग्राम निवेश से बिना अनुमति के निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

पृ.क.573/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./बिल्डिंग/2546 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक21/5/2024

प्रतिलिपि :–

1. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
2. एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
4. डायरेक्टर, जीओलॉजी एवं माईनिंग, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
5. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
6. सदस्य सचिव, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–II, विंग–3, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर–1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
7. कलेक्टर, जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. वनमण्डलाधिकारी, कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, जिला– रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

Nature Protects if She is Protected

Signature Not Verified
Digitally signed by: Shri P Arun Prasad
Designation: Member Secretary
Date and Time: 6/4/2024 5:07:04 PM